Dattopant Thengadi Foundation

दिनांक : 21 फरवरी, 2022

नया बजट : संभावनाएं व आशंकाएं

हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया। इस बजट के साथ भारत ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के माध्यम से आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने को चिह्नित किया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ने अमृत काल में प्रवेश किया है, और केंद्रीय बजट ने समग्र और भविष्य की प्राथमिकताओं के साथ अगले 25 साल के लिये (India@100) आर्थिक वृद्धि को आगे ले जाने का आधार रखा है।

बजट एक निश्चित अवधि के लिए संभावित आय और खर्च का ब्यौरा होता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 कहता है कि भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रतिवर्ष संसद में बजट पेश किया जाना चाहिए। केंद्रीय बजट पर पूरे देश की नजरें टिकी होती है ,क्योकि इसी से देश के आर्थिक भविष्य की रूपरेखा भी तय की जाती है। संसद में बताया जाता है कि पिछले साल सरकार की आय और व्यय कितनी थी,वर्तमान में कितनी है और अगले साल 'आय और व्यय' कितने होने की उम्मीद है। इस प्रकार इस बजट के माध्यम से सरकार पूरे देश को यह बताती है कि वह जनता की कमाई का एक-एक पैसा योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल कर रही है। बजट के माध्यम से ही देश की आर्थिक स्थिति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दर्शाया जाता है। हर मंत्रालय की कोशिश होती है कि बजट में उनके लिए अधिक से अधिक फंड आये और इसके लिए अक्टूबर-नवम्बर से वित्त मंत्रालय अन्य मंत्रालय के साथ बैठक करके एक ब्लू प्रिंट तैयार करता है और उसके बाद प्रत्येक मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा (negotiate) करते हैं।

देश ओमिक्रॉन की दहशत में था और बजट को लेकर सरकार को कई प्रतिस्पर्धी मांगों का सामना करना पड़ा। एक तरफ सरकार का राजकोषीय घाटा (या बाजार से कुल उधारी) चिंता का विषय था तो दूसरी ओर अर्थव्यवस्था में कमजोर वर्गों को निरंतर समर्थन देने की मांग की जा रही थी। इन मांगों के बीच सरकार ने 2022-23 में 39,44,909 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा, जो कि 2021-22 के संशोधित अनुमान से 4.6% अधिक है। बजट में विभिन्न योजनाओं व मंत्रालयों के लिए होने वाले आवंटन

को सुनकर अक्सर यह सवाल आम लोगों के मन में आता है कि सरकार के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? केंद्र सरकार के पास सबसे ज्यादा पैसा टैक्स और रेवेन्यू से आता है जिसमें टैक्स प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से प्राप्त किये जाते हैं। उधार व अन्य देनदारी (Borrowing & other liabilities), गैर-ऋण पूंजी प्राप्ति(non-debt capital receipts), कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर, इम्पोर्ट ड्यूटी, इत्यादि के माध्यम से सरकार अपने पास पैसे जुटाती है और आमतौर पर इन पैसों को केंद्र की योजनाएं, टैक्स व ड्यूटी में राज्यों का हिस्सा, सब्सिडी, डिफेंस, पेंशन, ब्याज भुगतान, आर्थिक सहायता और अन्य व्यय के लिए खर्च करती है।

केंद्रीय बजट 2022 सरकार के उच्च स्तर की आर्थिक वृद्धि, प्रौद्योगिकी सक्षम विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के उद्देश्य से विगत 1 फरवरी को प्रस्तुत किया गया जिसमें कहा गया कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2 प्रतिशत अनुमानित है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। सरकार ने डिमांड में तेजी लाने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर (Capital Expenditure) में भारी इजाफा किया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का लक्ष्य 7.5 लाख करोड़ रुपए रखा गया है जो पिछले वित्त वर्ष के लिए 5.5 लाख करोड़ रुपए थी। बजट से पूर्व आर्थिक जानकारों का कहना था कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में सुधार की रफ्तार में तेजी नहीं है और ऐसे में सरकार को हर हाल में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस करना होगा। इस बजट से युवाओं, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सीधे तौर पर मदद मिलने के आसार हैं। सरकार खुद निवेश को बढ़ावा देने की कमान संभालेगी और यह काम सरकार और निजी सेक्टर के जॉइंट वेंचर्स के जरिए किया जाएगा।

जब से यह द्वितीय डिजिटल बजट पेश किया गया है तब से आये दिन अख़बार में कई लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि यह बजट आम आदमी को खुश करने के लिए नहीं है और इसमें सबसे कमजोर वर्ग के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। कुछ का मानना है कि यह एक संतुलित व विकासोन्मुख बजट है। आमतौर पर सब लोग यह देखते हैं कि बजट में उनके दिलचस्प के क्षेत्र के लिए तुरंत क्या मिला है, और उसी के हिसाब से अपनी-अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। कई विशेषज्ञों ने बजट को समझते हुए सरकार के फ्यूचरिस्टिक एप्रोच को समझने का प्रयास किया है। पीएम गति शक्ति परियोजना के लिए 107 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जिसकी मदद से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नया रूप दिया जाएगा। इसके अंतर्गत रेल और सड़क सहित कुल 16 मंत्रालयों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। पीएम गति शक्ति को चलाने के लिए 7 इंजन है- सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे,बंदरगाह, जलमार्ग, जनपरिवहन, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इस कारण रोजगार के नए अवसर

देश में खुलेंगे और भारत विकास की एक नई रफ्तार पकड़ेगा। द इंडियन एक्सप्रेस में एक लेखक द्वारा कहा गया है कि यह बजट कृषि क्षेत्र की उपेक्षा करता है। सरकार ने देश के 1.63 करोड़ किसानों को गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया है। बजट भाषण में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन की बात की गयी है और 2023 को मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने का जिक्र किया गया है। फसल मूल्यांकन, लैंड रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए 'किसान ड्रोन' का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके साथ-साथ 'किसान सम्मान निधि' के तहत बजट में 68 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे 11 करोड़ किसानों को लाभ होगा। किसानों के लिए खाद्य और उर्वरक क्षेत्र में सब्सिडी की राशि में भारी वृद्धि की गई है, इसे 79 हजार करोड़ से बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार करोड़ कर दिया गया है।

किसानों को डिजिटल और हाइटेक सेवाएं देने के लिए पीपीपी मोड में एक योजना शुरू की जाएगी। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान और विस्तार संस्थानों के साथ-साथ निजी एग्रीटेक प्लेयर्स और स्टेकहोल्डर्स शामिल होंगे, जो कि एग्री वैल्यू चेन होंगे। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज स्कीम को पुनर्जीवित किया जाएगा। इससे सूक्ष्म व लघु उद्यमों को 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज मिल सकेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सहकारी समितियों के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं लेकिन प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों को को समर्थन के लिए उचित धन की आवश्यकता थी। बजट में इसका ध्यान रखते हुए 25 करोड़ का अलग से आवंटन किया गया है।

सामाजिक सेवाओं के तहत शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवार कल्याण, जलापूर्ति एवं स्वच्छता, आवास, शहरी विकास, श्रम एवं श्रमिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, पोषण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण इत्यादि पर भी विशेष ध्यान दिया गया है जिसमे 'वन क्लास-वन टीवी चैनल प्रोग्राम', नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, हर घर नल से जल, हाउसिंग फॉर आल, इत्यादि जैसे प्रोग्राम शामिल हैं। आम जनता के लिए स्वच्छ पानी और घर का प्रावधान एक 'गुणवत्ता व्यय' है। इसका आम जनता के जीवन-यापन के स्तर पर व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे सभी वेलफेयर प्रोग्राम के लिए सरकार को डायरेक्ट कोई रिटर्न नहीं मिलता। MGNREGA की आवंटित राशि को लेकर कई विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। इंडिया रेटिंग्स ने भी कहा है कि महामारी के बीच ग्रामीण भारत में जहां संकट बढ़ रहा है वहां मनरेगा के लिए प्रस्तावित फंड आवंटन में 20% से अधिक की कटौती चिंताजनक है। इस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में पिछले 2 वर्षों में जबरदस्त लीकेज देखा गया है। इस वर्ष केंद्र द्वारा इस कार्यक्रम के लिए 73,000 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है, पर ऐसा देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों से बिचौलिए इस योजना के तहत

लाभार्थियों का नाम दर्ज करने के लिए पैसे ले रहे हैं या फिर बड़े पैमाने पर अपने सगे-संबंधियों का नाम जोड़ रहे है। फ़िलहाल इस योजना को सख्त करने की जरुरत है।

बजट में युवाओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 14 क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव (PLI) के अंतर्गत अगले 5 वर्ष में 60 लाख नौकरियां आएंगी। इस बजट में पूंजीगत व्यय (CAPEX) को 5.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.2 लाख करोड़ कर दिया गया, यानी 40 प्रतिशत रोजगार सृजन के लिए जाएगा। PM GatiShakti को भी नौकरी और उद्यमशीलता के अवसर से जोड़ा गया है। इसके अलावा बजट में स्टार्ट अप्स और मेक इन इंडिया इत्यादि जैसे प्रोग्राम पर सरकार के जोड़ देने से इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन की कई संभावनाएं हैं। उदीयमान अवसर (Sunrise Opportunities): आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भू-स्थानिक प्रणालियों और ड्रोन, सेमीकंडक्टर तथा इसका इकोसिस्टम, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जीनोमिक्स एवं फार्मास्यूटिकल्स, हरित व स्वच्छ ऊर्जा आवागमन प्रणालियों में बड़े पैमाने पर सतत विकास में सहायता करने और देश के आधुनिकीकरण की अपार संभावनाएं हैं। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी योजनाओं से बिचौलियों को निकालने का काम किया गया है जो अब तक आम जनता का महत्वपूर्ण हिस्सा ले रहे थे। सरकार डिजिटल इकोनॉमी, फिनटेक को बढ़ावा देने के साथ-साथ NPA से निपटने के लिए बैड बैंक पर भी काम कर रही है।

बजट भविष्य में भारत को एक विकसित भव्य राष्ट्र बनाने की दिशा में एक कदम है जिसे शॉर्ट टर्म गेन पर नजर रखने के बजाय लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए तैयार किया गया है और इस बजट से नौकरी और अन्य क्षेत्रों में नई संभावनाएं दिख रही है। इसमें मिडिल क्लास के किये और भी प्रावधान हो सकते थे फिर भी कुल मिलाकर यह एक संतुलित और सर्व-समावेशी बजट है जिसमे पंक्ति के अंत में खड़े हर व्यक्ति का ध्यान रखा गया है।

***

हमारे प्रकाशन:

1) Democracy, Capitalism, Labour Movement: In Quest of Decent Work: https://www.suruchiprakashan.com/democracy-capitalism-labour-movement

2) Decent Wage : It’s not Just About Workers : https://www.suruchiprakashan.com/decent-wage

3) Industry 4.0 and the Future of Work(er) : https://www.suruchiprakashan.com/industry-4-0-and-the-future-of-work-er

मीडिया में DTF :

1) कट्टरपंथ की चुनौती और सामाजिक समरसता

2) चीन की खोखली समृद्धि और भारतीय दर्शन

3) शिक्षण संस्थानों में ड्रेस कोड का मामला